दैनिक भास्कर
भारत का सबसे बड़ा समाचार पत्र समूह
फरीदाबाद
मंगलवार, 3 जून, 2014
ज्येष्ठ, शुक्ल पक्ष 6, 2071

गुड़गांव-पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाते मुख्य अतिथि सार्थक अग्रवाल।

# पर्यावरण संरक्षण पर साउथ सिटी-टू में कार्यक्रम

भास्कर न्यूज | गुड़गांव

सोमवार को विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में साउथ सिटी की आरडब्ल्यूए ने सुधा सोसायटी में एक कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण को लेकर आरडब्ल्यूए पदाधिकारियों ने सुझाव दिए इस अवसर पर गुड़गांव निवासी सीबीएसई टॉपर सार्थक अग्रवाल कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। सार्थक गुड़गांव के सेक्टर-14 के निवासी हैं। वह दिल्ली के वसंत कुंज के डीपीएस का छात्र रहा है। 2014 में 12वीं में सार्थक सीबीएसई इंडिया टॉपर घोषित किया गया है। यह जानकारी सुधा सोसायटी के फाउंडर जीके भटनागर ने दी। इस अवसर पर साउथ सिटी-2 आरडब्ल्यूए अध्यक्ष एससी शर्मा भी मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि सार्थक अग्रवाल ने बच्चों को ऑटोग्राफ दिए।कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से साइकिल रैली भी निकाली गई, जिसको सार्थक अग्रवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके अलावा कार्यक्रम में कई तरह की पर्यावरण संरक्षण से संबंधित प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं, जिसके विजेताओं को भी सार्थक अग्रवाल ने पुरस्कार वितरित किए। इस अवसर पर साउथ सिटी टू व सुधा सोसायटी के पदाधिकारियों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसके अलावा दसवीं व 12वीं सीबीएसई में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्र-छात्रों को भी सम्मानित किया गया।

गुड़गांव
# जागरण सिटी
23 दैनिक जागरण नई दिल्ली, 22 मार्च 2014

## मेरा घोषणा पत्र

### ख्याति के अनुरूप शहर का विकास हो

- दिल्ली की तर्ज पर गुड़गांव में भी मेट्रो का जाल बिछे। परिवहन प्रणाली को सही किया जाना चाहिए।
- गुड़गांव से बड़े शहरों के लिए लग्जरी बसें चलाई जाएं।
- स्वास्थ्य सुविधा व शैक्षिक व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए
- शहर में चारों तरफ फैली गंदगी, बेतरतीब बिजली के तारों के जाल, सड़क पर घूमते जानवरों से शहर को मुक्ति मिले। शहर को सौंदर्यीकरण की दरकार है।
- गांवों में शौचालय, पीने के लिए स्वच्छ पानी, अस्पताल व स्कूल खोलने की व्यवस्था हो।
- सरकारी कार्यालयों की संख्या जोन सिस्टम से बढ़ाई जाए। प्रत्येक जोन में एकल विंडो सेंटर खुले।
- शहर व गांव में इस तरह की व्यवस्था से साइबर सिटी अपनी ख्याति के अनुरूप दिखे। इसके लिए एक बजट और एक टीम हो।
- निगम, हुडा,एचएसआइआइडीसी की जगह संघीय एजेंसी गुड़गांव विकास प्राधिकरण का गठन होना चाहिए।
- उद्यमियों से भी शहर के विकास में मदद ली जाए।
- पुलिस फोर्स की बढ़ोत्तरी के साथ महिला थाने व महिला पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए।
- बिजली के बड़े पावर स्टेशन के साथ भूमिगत केबिल लाइन डाली जानी चाहिए।

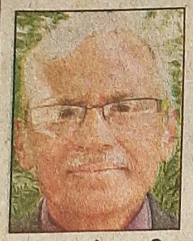



सुधा सोसायटी के प्रेसीडेंट जीके भटनागर

### रेलवे स्टेशन को मेट्रो से जोड़ा जाना चाहिए

- गुड़गांव शहर की मुख्य समस्या परिवहन व्यवस्था का दुरुस्त नहीं होना भी है।
- हुडा सेंटर मेट्रो स्टेशन से रेलवे स्टेशन के बीच मेट्रो चलाई जाए तो जाम की समस्या दूर हो जाएगी। घर के पास परिवहन सुविधा होगी तो दिल्ली आना जाना आसान हो जाएगा।
- इफको चौक, सिगनेचर टावर और राजीव चौक पर अंडरपास बनाने की जरूरत है। यहां पर हर पंद्रह मिनट पर जाम लग जाता है। समय खराब होता है, पेट्रोल बर्बाद होता है।. पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है।
- दिल्ली रोड, महरौली रोड और स्टेशन रोड पर सोडियम लाइट लगाई जाए ताकि सड़क पर प्रकाश व्यवस्था हो सड़क दर्शनीय बनें।
- पुराने शहर में महावीर चौक पर फुट ओवर ब्रिज बनाया जाए। जिसमें एस्केलेटर लगा हो। ताकि सड़क आर पार करने वालों को परेशानी न हो। इस चौक पर वाहनों के वजह से जाम की समस्या आम हो गई। इससे पैदल चलने वालों को मुक्ति मिलेगी।

राकेश शर्मा, सेंक्टर 4 निवासी, गुड़गांव

यदि आप भी अपना घोषणा पत्र जारी करना चाहते हैं तो हमें इस मेल/पते पर लिख भेजें...

pathaknamahry@nda.jagran.com

पता : एससीओ-42, सिविल लाइन गुड़गांव

गुड़गांव
# जागरण सिटी

खिलाड़ियों बारिश



www.jagran.com

जागरण सिटी
गुड़गांव

# बच्चों की तरह पेड़-पौधों को परवरिश की जरूरत

## सीमेंट-कंक्रीट व टाइल्स की जकड़न से सूख रहे पेड़

बत्म हो जाएगी हरियाली...साइबर सिटी के सेक्टर 15 पार्ट दो स्थित टाइल्स के बीच पेड़। जागरण

संवाददाता, गुड़गांव : इसे अधिकारियों रवाही कहें या फिर हरियाली के प्रति उदासीनता कि वह सीमेंट-कंक्रीट व क माध्यम से पेड़ों को जकड़ रहे हैं। इस में कैद पेड़ को हवा-पानी नहीं मिलता और परिणाम स्वरूप वह सूखने लगते हैं। पर्यावरण प्रेमियों का कहना है कि जिस प्रकार बच्चों की परवरिश करनी होती है उसी प्रकार पेड़-पौधों का ध्यान रखना होता है। तभी हरियाली बढ़ती है और पेड़ लंबे समय तक शुद्ध आबो-हवा देते हैं। यदि पर्यावरण को बेहतर करना है और प्रदूषण को कम करना है, तो अधिक से अधिक पौधे लगाने के साथ ही उनका रखरखाव पर सभी को जोर देना होगा।

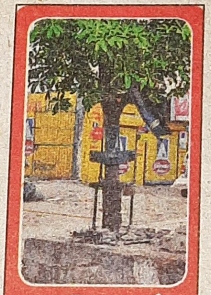

सांस तो लेने दो

सरकारी एजेंसी खानापूर्ति करते हुए पौधरोपण तो कर देती हैं लेकिन रखरखाव नहीं करने से सीमित पौधे ही पनप पाते हैं। अधिकारियों की लापरवाही का ही नमूना है कि वह पेड़ों का जीवन लेने पर तुली है। निगम, हुडा के इंजीनियरों ने पेड़ों को सीमेंट-कंक्रीट व टाइल्स से इस प्रकार जकड़ दिया कि उनकी जड़ों तक न तो पानी पहुंच पा रहा न ही हवा। बिना हवा-पानी के पेड़ का सूखना तय है। मानव संसाधन मंत्रालय में सलाहकार के रूप में काम कर चुके गोपाल कृष्ण भटनागर का कहना है कि जिस प्रकार बच्चों की देखभाल की जाती है उसी प्रकार पेड़-पौधों का ख्याल रखना जरूरी है। पेड़-पौधों के आसपास इतनी जगह होनी चाहिए कि उनकी जड़ों तक हवा-पानी पहुंच सके। साथ ही समय-समय पर गुड़ाई की जा

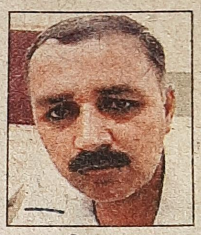

संदीप कुमार

गोपाल कृष्ण भटनागर

सके। जिस प्रकार शहर में कई जगह पेड़ों को सीमेंट-कंक्रीट व टाइल्स से जकड़ दिया गया उससे उनकी जड़ तक हवा-पानी नहीं पहुंच पाता है। इसके अभाव में वह सूखने लगते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पेड़ों के आसपास एक मीटर की जगह छोड़ने का प्रावधान बनाया हुआ है। अपने खर्चे से पेड़ों को संरक्षित करने में जुटे पर्यावरण प्रेमी संदीप कुमार का कहना है कि हमने अपने स्तर पर काफी प्रयास किया लेकिन अधिकारी नहीं चेत रहे। जकड़न के अलावा कई जगह पेड़ की शुरुआत में उसकी रक्षा करने वाले ट्रीगार्ड उसके बड़े होने पर एक बड़ी मुसीबत बन जाते हैं। जकड़न के कारण पेड़ों को आक्सीजन नहीं मिल पाती। वाटर लेवल नीचे होना एवं बारिश कम होने से पेड़ों को पर्याप्त नमी नहीं मिल पाती है। संदीप का कहना है कि पेड़ों के रखरखाव के लिए लोगों को भी आगे आना चाहिए।

Hi Society

VOL: 2 ISSUE: 7 23 - 31 October 2014 DELHI NCR



# A campaign for cleanliness

By a reporter

Keeping their pace with Swachh Bharat Abhiyan SUDHA Society the leading NGO of the city in association with RWA south city A1 block launched Swachh Bharat Swachh colony recently.

The students, parents, along with RWA Management Committees participated in this programme. While taking Broom, and wearing Mask and Gloves large number of children and parents participated in the Programme. Ladies also took part in the cleanliness drive in spite of pooja festival. Before that G K Bhatnagar, President Sudha Society welcomed the Chief Guest and Guest. Followed by this 13 Children sung the" Hom ho ge kamyab" song which was appreciated by the guests and gathering. The following students won the prizes on slogan and Painting which was given by the chief Guest. In painting -1st Prize –Anaanya Agarwal, 2nd prize Vani tyagi , 3rd Prize Anwita Agarwal, In slogan – 1st Prize Advit Goyal 2nd Prize Himalya joshi 3rd Prize Devansh Tyagi.

# जगा लोगों को विश्वास, पूरी होगी जीडीए की आस

- गुड़गांव विकास प्राधिकरण के गठन के सांसद भी हिमायती
- एजेंसी के गठन के बाद तेजी से होगा गुड़गांव का विकास



रोड पर अतिक्रमण व अवैध रूप से बनी पार्किंग की वजह से गुरुद्वारा रोड पर इस तरह लगा रहता है जाम।

अतुल कटारिया चौक की खस्ताहाल सड़क।


पाइप डालने के लिए बनी बनाई सड़क को इस तरह तोड़ दिया जाता है।

शहर की लक्ष्मण विहार की मुख्य सड़क पर जमा सीवर का पानी।

सत्येंद्र सिंह, गुड़गांव




**औद्योगिक विकास** के पंख लगा छोटा गुड़गांव शहर आटो, आईटी व चिकित्सा हब बन चुका है। यहां देश ही नहीं विदेश के लोग भी रह रहे हैं। लेकिन विकास की बात करें तो ख्याति के अनुरूप गुड़गांव विकास पथ पर नहीं चल सका। जर्जर सड़क, ट्रैफिक जाम, उफनते सीवर और बिजली पानी की समस्या सदैव मुंह बांये खड़ी रहती है। समस्या की वजह है शहर मे एकल विकास एजेंसी का न होना। एक एजेंसी सड़क बनाती है तो दूसरी सीवर लाइन या पेयजल लाइन बिछाने के लिए जेसीबी चला देती है।

जिसके चलते जनता के जेब से ही निकाली गई सरकारी रकम खर्च तो हो जाती है पर लाभ जनता को नहीं मिलता। हाय-तौबा मचाया तो हुडा विभाग के अधिकारी नगर निगम पर और नगर निगम के अधिकारी हुडा विभाग या फिर एचएसआइआइडीसी पर ठीकरा फोड़ देते हैं। इन हालातों में शहर का ढांचागत विकास नहीं हो पा रहा है। कई योजनाएं दो विभागों के पाट (किनारे) पर लटकी हुई है। सिटी आउटडोर सर्विलांस योजना, कई इलाकों में बनने वाले फ्लाईओवर इस बात की बानगी हैं। ढांचागत विकास तभी संभव होगा जब शहर में दिल्ली या दूसरे मेट्रो शहरों की तर्ज पर एकल विकास एजेंसी गुड़गांव विकास प्राधिकरण का गठन होगा।

एजेंसी गठित करने की मांग करीब दस साल से यहां की जनता कर रही है। कई दफा जनता के मंच से सांसद राव इंद्रजीत सिंह भी जीडीए बनाए जाने की वकालत कर चुके हैं। अब जब विकास की राजनीति करने का दावा कर केंद्र में मोदी सरकार बनने जा रही और राव इंद्रजीत सिंह मोदी रथ पर बैठ संसद फिर पहुंच चुके हैं तो लोगों की अपेक्षाएं और भी बलवती हो गई हैं। देखना है कि जनता की अपेक्षाओं पर कितना खरा उतरते हैं।

## जागरण सुझाव

शहर के विकास के लिए एकल एजेंसी का होना जरूरी है। क्योंकि अभी हुडा या नगर निगम व अन्य जो एजेंसी अलग-अलग क्षेत्र में कार्य कर रही उनमें आपसी तालमेल का अभाव है। उनके अधिकारी भी वरिष्ठता को लेकर एक दूसरे के साथ बैठ साझा प्लान बनाने में अपनी तौहीन समझते है। जब भी बैठक होती है तो कनिष्ठ अधिकारी ही दिखाई देते हैं। जिसके चलते बैठक एक औपचारिकता बन जाती है। शहर की कई महत्वपूर्ण योजना अधर में लटकी हैं। जब एक एजेंसी होगी और उसका प्रमुख सबसे वरिष्ठ होगा तो विकास का एजेंडा सही रूप से तय होगा। सड़क बनाने वाली विंग का सभी अन्य विंग से यह जानकारी लेनी होगी कि उन्हें तो कोई लाइन नहीं बिछानी।

### पांच साल में विकास पर खर्च धनराशि, व वर्तमान हालात

**सड़क** : करीब सात सौ 20 करोड़ : फिर भी एक भी सड़क सही नहीं, कई सड़कों को बनने के बाद पाइप लाइन डालने के लिए खोद दिया गया, मोर चौक से सोहना अड्डा व रेलवे रोड हालिया उदाहरण

**पेयजल** : दो करोड़ खर्च, कई जगह प्रोजेक्ट दूसरे विभाग की टांग में फंसे

**बिजली** : डेढ़ सौ करोड़ पर शहर के लगभग सभी फीडर ओवर लोड

**सीवर लाइन** : सवा सौ करोड़, पर मास्टर लाइन से अन्य लाइन को अभी भी कनेक्ट नहीं किया गया जिसके चलते बरसात में सीवर का पानी उल्टे सड़क पर दिखता है।

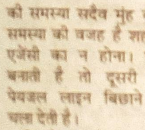

"देखिए, गुड़गांव ने जो भी विकास किया प्राइवेट क्षेत्र की बदौलत पाया। बिल्डर या कालोनाइजर ने भी इसी इलाके में सुविधा दी जहां से उसे लाभ मिला। शहर का ढांचागत विकास नहीं हुआ। हमें एक समस्या हल कराने के लिए कई विभागों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। समुचित विकास तभी सम्भव है जब एकल एजेंसी हो जिसको पूरे क्षेत्र की मानिटरिंग करने के साथ योजनाएं भी बनाए।

-एलआर यादव, सेवानिवृत्त कमांडेंट बीएसएफ।



"गुड़गांव के विकास के लिए जीडीए का गठन हर हाल में होना चाहिए। विकास तभी होगा इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। अभी जो हालत है उसमें कोई भी एजेंसी ऐसा विजन नहीं बना रही जिससे शहर का ढांचागत विकास हो। फिर यह मांग तो क्षेत्र हित में सासंद भी करते आए हैं। अब तो उन्हें अपनी आवाज और भी बुलंद करनी चाहिए।

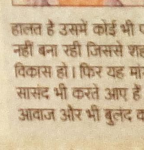

-टीसन कौल, प्रेसीडेंट आरडी सिटी आरडब्ल्यूए (सेवानिवृत्त सहायक निदेशक तकनीकी शिक्षा विभाग दिल्ली)



"दिल्ली में डीडीए की तर्ज पर गुड़गांव में भी एक विकास एजेंसी होनी चाहिए और एक ही छ[illegible] के नीचे सारे काम हो। लोगों की हेल्प के [illegible] जोनल आफिस जरूर हों। अन्यथा एक [illegible] बनाएगी तो दूसरी एजेंसी के लोग तोड़ [illegible] खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ेगा। कुछ अधिकारी तो चाहेंगे ही कि जितनी बार स[illegible] बने ताकि उन्हें फायदा हो। सांसद से उम्[illegible] कि लाखों लोगों की आस को वह जरूर [illegible] करेंगे। बस उन्हें इच्छा शक्ति दिखाने की [illegible] जरूरत लोग खुद उनके साथ खड़े मिलेंगे

-डीके [illegible]
निवासी सेक्टर 46 गुड़गांव, सेवानिवृ[illegible] सलाहकार मानव संसाधन मंत्राल[illegible]

गुड़गांव
जागरण सिटी
15
दैनिक जागरण
नई दिल्ली, 19 मार्च 2014

# साउथ सिटी में नहीं है एक भी खेल का मैदान

वादा तेरा वादा

जागरण संवाददाता, गुड़गांव : एक दशक से जब भी लोकसभा व विधानसभा का चुनाव होता है। साउथ सिटी में रहने वाले युवा व उनके घर वाले कालोनी में खेल मैदान बनाए जाने की मांग करते हैं। करीब आठ हजार मतदाता वाली कालोनी के लोगों से उम्मीदवार वादा भी करते लेकिन चुनावी नैया पार करते ही वादा भूल जाते हैं। प्रदेश के खेल मंत्री के आगे भी यह मसला रखा गया लेकिन वादे के सिवा कुछ नहीं मिला। वादाखिलाफी से परेशान कालोनी के लोगों ने एक बाद फिर इस मुद्दे का हवा दे दी है।

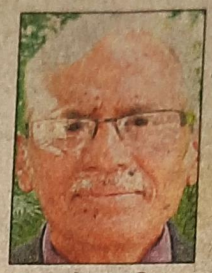

सुधा सोसायटी के प्रेसीडेंट जीके भटनागर

- कई सालों से मांग कर रहे यहां के रेजीडेंट
- चुनाव के समय उम्मीदवार भी बन जाते हैं समर्थक

"लोगों की मांग हमारे पास पहुंची, उस पर अपने स्तर जो कार्रवाई होगी की जाएगी। आचार संहिता के चलते किसी तरह के दावे नहीं किए जा सकते।

-पीसी मीणा, हुडा प्रशासक गुड़गांव।

सामाजिक संगठन सुधा सोसायटी ने तो प्रशासन व हुडा विभाग को पत्र लिखकर साउथ सिटी टू खेल मैदान बनाने की मांग की है। यही नहीं वोट मांगने आने वाले उम्मीदवारों के आगे भी इस मांग को पुरजोर तरीके से रखने का प्लान बना लिया गया है। सोसायटी के प्रेसीडेंट जीके भटनागर ने कहा कि कालोनी में कई राज्यों से सेवानिवृत्त अधिकारी परिवार सहित रह रहे हैं। खेल मैदान न होने से युवा, बच्चे बुजुर्ग परेशान हैं। जबकि सेवानिवृत्त अधिकारियों की इस तरह की अन्य शहरों में सोसायटी है वहां प्रशासन ने खेल मैदान मुहैया करा रखा है। जबकि कालोनाइजर एरिया होने के चलते यहां ध्यान नहीं दिया गया। राहुल, व मनोज ने कहा कि प्रदेश सरकार एक ओर तो खेल को बढ़ावा देने की बात कह रही है। दूसरी ओर लोगों को खेल मैदान तक नहीं मुहैया कराए जा रहे हैं। जबकि किसी भी कालोनी के प्लान में खेल का मैदान, सामुदायिक भवन, अस्पताल, स्कूल मुख्य सुविधाओं को पहले शामिल किया जाता है।

# आज समाज

वर्ष-8, अंक-151, नई दिल्ली, पृष्ठ-10, मंगलवार, 3 जून 2014, शक संवत 1936, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष 6, वैशाख मास, 21 प्रविष्टे, 04 शाबान हिजरी 1435, षष्ठी, मूल्य 2


## वर्ल्ड पर्यावरण डे पर प्रतियोगिता

गुड़गांव। आर्ट ऑफ लिविंग की ओर से सुधा सोसाइटी व आरडब्ल्यूए साउथ सिटी-2 ने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का आयोजन किया। इस अवसर पर सीबीएसई इंडिया टॉपर सार्थक को गैस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किया गया था। आरडब्ल्यूए प्रेजिडेंट विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। इस दौरान सुधा सोसाइटी की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें स्थानीय लोगों के साथ साथ बच्चों ने बढ़चढ़कर भाग लिया। इस दौरान असीन खरे ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर कविता प्रस्तुत की। इस दौरान क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिताओं में विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया।

दैनिक जागरण
न की राजनीति कर रही भाजपा : मनमोहन 14
निशानेबाजी विश्वकप में
gran.com
दिल्ली • उत्तर प्रदेश • मध्य प्रदेश • हरियाणा • उत्तराखण्ड • बिहार • झारखंड • पंजाब • जम्मू-कश्मीर
6 | दैनिक जागरण www.jagran.com नई दिल्ली, 30 मार्च 2014

# लोकतंत्र के स्तंभ चार फिर भी लाचार

ब्रिटिश काल का कानून एक नक्शे की तरह था, जिसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन कर अपने अनुकूल इमारत खड़ी की जा सकती थी। बदलाव भी हुआ लेकिन जरूरत के मुताबिक नहीं। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के साथ चौथे स्तंभ के रूप में मीडिया भी समुचित बदलाव लाने में असमर्थ रही। यह बात कानून विशेषज्ञों ने जन जागरण के तहत आयोजित कानून सुधार विषय पर परिसंवाद में कही। पेश है परिसंवाद के प्रमुख अंश :

श्री जेबी शर्मा, सेवानिवृत्त सत्र न्यायाधीश

- कानून के अंदर कमजोरियां आती है, तब समस्याएं पैदा होती है।
- कानून व्यवस्था में बदलाव को प्राथमि[illegible] दी गई।
- कार्यपालिका शून्यता को नहीं भर पाई। तब न्यायपालिका का आगे आना पड़ा।
- राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी रह गई। इसलिए न्यायपालिका हावी है।
- अधिकारी वर्ग ने भी कभी आगे आकर बदलाव का प्रयास नहीं किया।
- सीपीसी व सीआरपीसी में बदलाव की जरूरत है।

श्री आरएस राघव, पूर्व अध्यक्ष गुड़गांव बार कौंसिल

- जिन कानूनों की दरकार ही नहीं है। उन्हें हटा दिया जाना चाहिए।
- ऐसे कई मामले हैं, जो वर्षो से अदालतों में चल रहे हैं।
- महत्वपूर्ण मामलों के निपटारे के लिए भी प्राथमिकता तय नहीं की गई।
- सीआरपीसी में सुधार कर तीन तारीखों में मामले निपटाने की बात कही गई।
- चार्जशीट के बाद देरी से बचने के लिए साक्ष्य अधिनियम में बदलाव की जरूरत है।
- भूमि कर कानून सबसे पुराना ( 1876) है, आज के संदर्भ में नुकसानदेह है।

श्री जीके भटनागर पूर्व मुख्य सलाहकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार

- एक अर्से से कानून में बदलाव के लिए जरूरत महसूस होती रही है।
- कानून में बदलाव की स्वच्छ मंशा कभी नहीं रही।
- न्यायपालिका समय सीमा को सख्ती से पालन नहीं करा पाई।
- इस कानून के माध्यम से ब्रिटिश काल में शोषण हो रहा था।
- आज कमजोर कानून की आड़ में बलात्कारी बच रहे हैं।
- लोकतंत्र के चार स्तंभ हैं। फिर भी कानून में सुधार नहीं हो पा रहा है।

श्री कुलभूषण भारद्वाज पूर्व अध्यक्ष बार कौंसिल, गुड़गांव

- अभी भी लोगों को मानसिक रूप से आजादी नहीं मिली है।
- जो भी आज तक कानून में सुधार हुआ है। सिर्फ स्वार्थ की पूर्ति के लिए।
- आजादी के बाद वोटों की खातिर बहुत बदलाव हुए।
- व्यवस्था के बावजूद न न्याय सुलभ है न सस्ता रह गया है।
- परिवार को देखते हुए अपराध को कम आंकने की परंपरा खत्म हो।
- सजा में बदलाव के लिए किसी तरह के बहाने बाजी पर रोक लगे।

वीना गुप्ता, सुरक्षा विशेषज्ञ

- महिलाओं व बच्चों के लिए अभी तक विशेष कानून नहीं बनाए गए।
- पीड़ित महिलाओं को बार बार अदालत का सामना करना पड़ता है।
- वहीं अपराधी बिना किसी परवाह के मुक्त रूप से घूमता रहता है।
- कानून के रखवालों के यहां बाल श्रम अवरोधक कानून की धज्जियां उड़ रही है।
- जबतक उनके लिए रोजी रोटी की व्यवस्था नहीं की जाती। उनके साथ अन्याय होगा।
- वैसा कानून बने जिससे की लोगों को शकून मिले।

## शासन उत्कृष्टता में

जागरण विचार

हम एक ऐसे देश है जहां कानूनों की कोई कमी नहीं। हर छोटी-बड़ी समस्या के लिए कानून बने हुए हैं, जिनमें समय के साथ सुधार भी होते रहते हैं। इतना ही नहीं हमारे राजनेता अमुक-अमुक समस्या का उल्लेख करते हुए उनके हल के लिए कानून बनाने के वायदे भी करते रहते हैं। यह रवैया समस्याओं को सुलझाने नहीं, बल्कि उन्हें जटिल बनाने वाला है। जरूरत हर मसले के लिए कानून बनाने की नहीं, बल्कि उनके प्रभावी अमल की है। ऐसे कानून व्यर्थ हैं जिनका सही ढंग से इस्तेमाल न हो। जब कानूनों के अमल में भेदभाव होता है तो वे अन्याय के प्रतीक बन जाते हैं।